www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 156 | जौनपुर मंगलवार, 20 जनवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता से भारतीय मेडिकल छात्र चिंतित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बांग्लादेश में हाल के महीनों में आई तेज राजनीतिक उथल–पुथल और भारत–विरोधी भावना के उभार ने वहां रह रहे हजारों भारतीय छात्रों, खासकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों, को गहरी चिंता में डाल दिया है। वर्षों तक अपेक्षाकृत सुरक्षित और किफायती शिक्षा के लिए पसंदीदा गंतव्य रहा बांग्लादेश अब अनिश्चितता और डर के माहौल से घिरता दिख रहा है। मौजूदा हालात में नौ हजार से अधिक भारतीय मेडिकल छात्र वहां नामांकित हैं, जो भारत के महंगे निजी मेडिकल कॉलेजों के विकल्प के तौर पर बांग्लादेश की कम ट्यूशन फीस और सांस्कृतिक निकटता के कारण यहां पहुंचे थे। एक अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2024 तक भारतीय छात्रों के लिए बांग्लादेश का शैक्षणिक माहौल अपेक्षाकृत सहज और स्थिर था। भारतीय छात्र ढाका और अन्य शहरों के मेडिकल कॉलेजों में न केवल पढ़ाई कर रहे थे, बल्कि स्थानीय शैक्षणिक जीवन में भी सहजता से घुलमिल गए थे। हालांकि, अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के साथ ही हालात तेजी से बदले। सत्ता परिवर्तन के बाद देश में राजनीतिक तनाव, विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं में इजाफा हुआ, जिसका असर विदेशी छात्रों पर भी दिखने लगा ।

सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने शनिवार को केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर एक पोस्ट में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से परामर्श करने के बाद, केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक आयुमंतकथ को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।यह नियुक्ति सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुरूप है, जिसने पहले केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव दिया था। न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्ताक का जन्म 1 जून, 1967 को हुआ था और वे केरल के कन्नूर जिले के थाना के मूल निवासी हैं। उन्होंने वीबी कॉलेज ऑफ लॉ, उडुपी से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में एमजी विश्वविद्यालय से लेबर लॉ में एलएलएम की उपाधि प्राप्त की।उन्होंने 1 अक्टूबर, 1989 को अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया ।

जनता दर्शन में आई महिला ने सीएम योगी को बताई समस्या

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह श्जनता दर्शनश किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए हर फरियादी की समस्या सुनी और निराकरण के लिए अफसरों को निर्देश दिया। इस दौरान लखनऊ निवासी महिला सीमा ने मुख्यमंत्री से आर्थिक विपन्नता का जिक्र किया और पति द्वारा घर से निकाले जाने की शिकायत की। आग्रह किया कि उन्हें घर में रहने की जगह दिलाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त को तत्काल उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। लखनऊ निवासी सीमा अपनी दो बच्चियों को लेकर सोमवार को जनता दर्शन में पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ससुर का निधन हो गया है। पति व ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। दो छोटी बच्चियों को लेकर वह भटक रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से उन्हें वापस ससुराल में भिजवाने तथा वहां रहने देने के लिए गुहार लगाई। महिला ने बच्चों के लालन–पालन के लिए आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस आयुक्त को मामले में तत्काल उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अपने माता–पिता के साथ आए सभी बच्चों को चॉकलेट दी और मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। इस दौरान मां सीमा के साथ दो साल की नन्ही अनन्या भी आई थी। मुख्यमंत्री ने उसे भी चॉकलेट दी और दुलार किया। चॉकलेट पाकर बच्ची खिलखिला उठी। जब मुख्यमंत्री ने उससे चॉकलेट मांगी तो उसने बड़ी मासूमियत से चॉकलेट वापस सीएम की तरफ बढ़ा दी। यह देखकर मुख्यमंत्री का बालप्रेम उमड़ पड़ा। इस दौरान नन्ही बच्ची की भाव भंगिमा और मुख्यमंत्री का संवाद देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भाव–विभोर हो गया। श्जनता दर्शनश में मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस, बिजली विभाग के साथ ही आर्थिक सहायता से जुड़े प्रकरण भी आए। मुख्यमंत्री ने सभी से मिलकर उनका प्रार्थना पत्र लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर प्रकरण की जांच कराकर फरियादियों की समस्याओं को हल कराएं। इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने आए फरियादियों से अस्पताल से एस्टिमेट मंगाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर सुख दुःख में प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। सरकार आपकी हर उचित समस्या का निदान कराएगी।

अमित शाह ने आपदा राहत बल के साहस को किया सलाम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह 'आपदाओं के दौरान राष्ट्र के भरोसे का स्तंभ' बन गया है। शाह ने बल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आपदाओं से निपटने में सक्षम भारत के निर्माण के मोदी सरकार के संकल्प को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से एनडीआरएफ आज आपदाओं के दौरान राष्ट्र के विश्वास का स्तंभ बन गया है। उन शहीदों को सलाम, जिन्होंने दूसरों की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। गृह मंत्री ने इस दौरान उन जवानों को भी याद किया जिन्होंने राहत कार्यों के दौरान दूसरों की जान बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा, ष्मैं उन वीर शहीदों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। 2006 में स्थापित ने पिछले दो दशकों में प्राकृतिक और मानव–निर्मित आपदाओं के दौरान अपनी कार्यक्षमता को वैश्विक स्तर पर साबित किया है। चाहे वह भूकंप हो, चक्रवात हो या बाढ़,के जवान हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। यह बल रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों से निपटने में भी सक्षम है। तकनीकी कौशल अत्याधुनिक उपकरणों और मलबे के नीचे फंसे लोगों को खोजने वाली आधुनिक मशीनों से लैस। अमित शाह के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्रतिक्रिया–केंद्रित से तैयारी–केंद्रित आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया है।

राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के जिला इकाई अध्यक्षों को संबोधित करेंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड के पार्टी के जिला इकाई अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को हरियाणा के जिला इकाई अध्यक्षों को संबोधित करने के बाद यहां पत्रकारों को बताया कि गांधी 21 जनवरी को यहां पहुंचेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा और उत्तराखंड में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में इन राज्यों के जिला इकाई अध्यक्षों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। कुरुक्षेत्र में 13 से 22 जनवरी तक आयोजित इस शिविर में हरियाणा के 33 और उत्तराखंड के 27 जिला अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। हुड्डा ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आय बढ़ने के बजाय उनकी लागत कई गुना बढ़ गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप भी लगाया। हुड्डा ने दावा किया कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सभी महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन अब यह लाभ केवल सीमित संख्या में महिलाओं को ही मिल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेने वाले नए अधिनियम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हुड्डा ने कहा कि भाजपा नीत सरकार ने दलितों, पिछड़े वर्गों, गरीबों, ग्रामीणों और पंचायतों के अधिकारों पर हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में आठ लाख से अधिक मनरेगा कामगार होने के बावजूद, 2024–25 के दौरान केवल 2,100 परिवारों को ही 100 दिन का काम उपलब्ध कराया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीशन साउथ तमिलनाडु में जल्द करेंगे मेगा रैली

तमिलनाडु , (एजेंसी)। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सिर्फ चार महीने बचे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर मदुरंथकम में एक विशाल रैली के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए चुनावी बिगुल बजाने वाले हैं। जानकारी के अनुसार, इस भव्य जनसभा ने राज्य भाजपा नेतृत्व को पूरी तैयारियों में जुट जाने को मजबूर कर दिया है। ऐसी चर्चाएं तेज हैं कि यह रैली एनडीए में शामिल होने वाले नए सहयोगियों की औपचारिक घोषणा का मंच बन सकती है। तमिलनाडु में एनडीए का नेतृत्व कर रही एआईएडीएमके ने पहले ही संकेत दे दिया है कि अभिनेता विजयकांत की डीएमडीके के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि, भाजपा ओ पन्नीरसेल्वम और एएमएमके नेता टीटीवी दिनाकरन को गठबंधन में शामिल करने के लिए उत्सुक है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने व्यक्तिगत मतभेदों के कारण ओपीएस को शामिल करने पर सहमति नहीं दी है। दिनाकरन का एनडीए में शामिल होना संभव है और इसकी घोषणा 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में की जा सकती है। एआईएडीएमके ने पीएमके के एक गुट के साथ गठबंधन कर लिया है। पार्टी के संस्थापक डॉ. रामदास द्वारा अपने बेटे अंबुमणि रामदास को निष्कासित करने के बाद पार्टी में फूट पड़ गई है। पिता ने अभी तक गठबंधन को लेकर अपना अंतिम रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि अंबुमणि पहले ही एआईएडीएमके के साथ जुड़कर एनडीए का समर्थन कर चुके हैं। राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके–कांग्रेस गठबंधन को चुनौती देने के लिए एआईएडीएमके और भाजपा दोनों ही एक मजबूत एनडीए गठबंधन बनाने के लिए आक्रामक प्रयास कर रही हैं। अभिनेता विजय की पार्टी (टीवीके) का उदय भी आगामी चुनाव में एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है।

जब काम ठीक से चलने लगे तो पुरानी पीढ़ी को हट जाना चाहिए : नितिन गडकरी

नागपुर, (एजेंसी)। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इशारों–इशारों में बड़ा बयान दिया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगें तो पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के लिए रास्ता बना देना चाहिए। उन्होंने यह बात नागपुर में एडवांटेज विदर्भ– खासदार औद्योगिक महोत्सव के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही।गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और पुरानी पीढ़ी को धीरे–धीरे पीछे हटकर अन्य काम करने चाहिए।यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 'एडवांटेज विदर्भ–खासदार औद्योगिक महोत्सव' को लेकर थी, जिसकी परिकल्पना खुद नितिन गडकरी ने की है। इस आयोजन का आयोजन एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (एआईडी) के अध्यक्ष आशीष काले द्वारा किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य विदर्भ को भारत के औद्योगिक नक्शे पर एक मजबूत और उभरते हुए विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है।गडकरी ने कहा कि आशीष काले ने 'एडवांटेज विदर्भ' पहल में युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया है, जो एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि धीरे–धीरे पीढ़ी को बदलना चाहिए। आशीष के पिता मेरे मित्र हैं। अब समय आ गया है कि हम जैसे लोग धीरे–धीरे रिटायर हों और जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपें। जब गाड़ी ठीक से चलने लगे, तब हमें पीछे हटकर कोई और काम करना चाहिए।एआईडी के मुख्य मार्गदर्शक नितिन गडकरी ने आगे बताया कि एडवांटेज विदर्भ एक्सपो का यह तीसरा वर्ष है। यह औद्योगिक प्रदर्शनी 6 से 8 फरवरी तक नागपुर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे और प्रतिभाशाली उद्यमी मौजूद हैं।गडकरी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तीन सेक्टर बेहद अहम होते हैं।

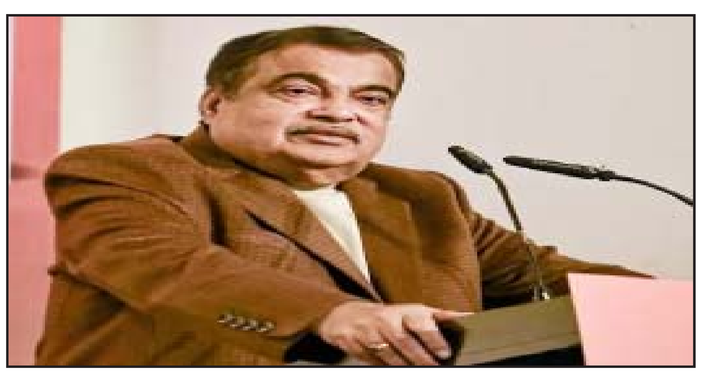

मुख्यमंत्री भगवंत मान का अजनाला दौरा, सरकारी डिग्री कॉलेज का करेंगे शिलान्यास

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सोमवार को अमृतसर जिले के अजनाला दौरे पर हैं और इस दौरे में वे अजनाला क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अमृतसर दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरान वे सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र अजनाला में सरकारी डिग्री कॉलेज की नींव रखेंगे। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री अजनाला के गांव बिकराऊर में बनने वाले सरकारी डिग्री और वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। यह वही वादा है, जो साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने जनता से किया था। अब इस वादे को पूरा किया जा रहा है, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अजनाला विधानसभा क्षेत्र के लिए यह दिन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि यहां लंबे समय से सरकारी डिग्री कॉलेज की मांग उठाई जा रही थी। क्षेत्र के युवाओं और अभिभावकों को उच्च शिक्षा के लिए अमृतसर या दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की परेशानी होती थी। अब सरकारी डिग्री कॉलेज खुलने से अजनाला और आसपास के गांवों के छात्रों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। इस कॉलेज का लाभ सिर्फ अजनाला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीमावर्ती तीन विधानसभा क्षेत्रों के कई गांवों के युवाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए यह कॉलेज एक बड़ा सहारा साबित होगा। बेहतर शिक्षा मिलने से यहां के युवा आगे बढ़ सकेंगे और अपने भविष्य को मजबूत बना सकेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दाना मंडी अजनाला में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है।

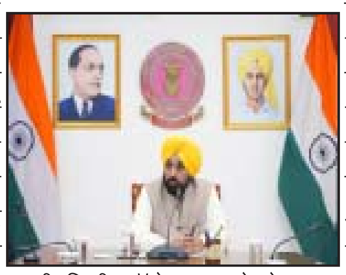

धरातल पर काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता देती है भाजपा : विजय सिन्हा

पटना, (एजेंसी)। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितन नबीन के नामांकन को राज्य के लोगों के लिए श्गौरव का पलश बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश के लोगों के बीच में यह संदेश गया है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व धरातल पर काम करने वाले लोगों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने सोमवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि इस बात को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में युवा बल को तवज्जो दी जा रही है। उन पर भरोसा जताया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि नितिन नबीन के नेतृत्व में आगामी दिनों में पार्टी धरातल पर बेहतर करने में सफल होगी। हमारी पार्टी में हर प्रकार के चुनाव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संपन्न किया जाता है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि नितिन नबीन का नामांकन दाखिल किया जाना इस बात का प्रतीक है कि हमारी पार्टी में युवाओं की आवाज सुनी जाती है। हम उन्हें अनदेखा करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। हमें विश्वास है कि आगामी दिनों में इसका दूरगामी असर होगा। इससे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस खास मौके पर मैं नितिन नबीन को शुभकामाएं देना चाहूंगा। वो आज की तारीख में युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आगामी दिनों में देश प्रदेश के कई युवा उनसे प्रेरित होंगे। उन्होंने पटना गर्ल्स हॉस्टल के प्रकरण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में बिहार में कानून का राज स्थापित है। रही बात तेजस्वी यादव की, तो उन्हें यह समझना होगा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को हमारी सरकार नहीं छोड़ती है। तेजस्वी यादव को किसी भी प्रकार का बयान देने का कोई नैतिक हक नहीं है। ये लोग ही कभी अराजकता के प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने कहा कि जो लोग भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, मौजूदा समय में उन्हें चिन्हित करने की कवायद जारी है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

महाराणा प्रताप से हुई नीतीश कुमार की तुलना, जेडीयु नेता ने बताया बिहार का सेवक

बिहार, (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर एएनआई से बात करते हुए, जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद और कार्यक्रम के आयोजक संजय झा ने मुख्यमंत्री की तुलना महाराणा प्रताप से करते हुए उन्हें षबिहार का सेवक बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने समाज के सभी वर्गों के लिए और उनके साथ काम किया, उसी प्रकार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सभी का समान रूप से ख्याल रखते हैं। वे महाराणा प्रताप की तरह ही नायक हैं। जहां महाराणा प्रताप ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, वहीं हमारे मुख्यमंत्री बिहार की जनता के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। वे बिहार के सेवक हैं। इस बीच, मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी के उपाध्यक्ष महाराणा प्रताप की स्मृति में प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की भागीदारी पर भी प्रकाश डाला। मंत्री ने सामाजिक सद्भाव के लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों को याद करने के लिए ऐसे अवसरों को मनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष संजय सिंह महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं... वे समाज में महाराणा प्रताप के सामाजिक सद्भाव के संदेश के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे हैं।

इस वर्ष भी पुण्यतिथि मनाई गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें शामिल हुए। सामाजिक सद्भाव के लिए काम करने वाले ऐसे महान व्यक्तित्वों की पुण्यतिथि मनाना समाज में सद्भाव को बढ़ावा देता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 को हुआ था। राजस्थान के मेवाड़ के इस राजपूत शासक ने 1576 में अकबर के साथ हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पश्चिम चंपारण के बेतिया से श्समृद्धि यात्राश का शुभारंभ किया।

यह उनकी राज्यव्यापी 17वीं यात्रा है और मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभालने के बाद से यह उनकी 15वीं यात्रा है।

संपादकीय

पतंगबाजी में मगन सरकार

असम के कालियाबोर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस पर एक बेहूदा टिप्पणी की। इन चुनावों में भाजपा ने कई निगमों पर अपना कब्जा जमाया है और सबसे बड़ी जीत तो बृहन्नमुंबई नगरपालिका में मिली है, जहां भाजपा ने शिवसेना को पीछे कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस को चौथा स्थान मिला है, जिस पर अपनी जीत का घमंड दिखाते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का जन्म 1885 में मुंबई में हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण पहले स्थान पर नहीं आ पाई। कांग्रेस ने देश का भरोसा खो दिया है क्योंकि उसके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई है ।असम चुनावों में महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनावों का जिक्र कर और उसमें भी कांग्रेस की हार पर टिप्पणी कर प्रधानमंत्री मोदी क्या हासिल करना चाहते हैं, यह समझना कठिन नहीं है। दरअसल उनकी सबसे बड़ी कुंठा ही यही है कि वे कांग्रेस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। नेहरूजी से लेकर राहुल गांधी तक के लिए तमाम अपमानजनक और अक्सर झूठी बातें कहने के बावजूद गांधी परिवार को धर्मनिरपेक्ष राजनीति से डिगा पाने में नरेन्द्र मोदी असफल रहे हैं, इसलिए उन्हें चुनावी जीत के बावजूद खुशी नहीं मिल पा रही ।यूं भी नरेन्द्र मोदी चुनाव दर चुनाव जीतने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को कहां पूरा कर पा रहे हैं, उनकी जगह राहुल गांधी ही पीड़ितों के आंसू पोंछते नजर आते हैं। अभी इंदौर में ही कम से कम 24 लोगों की मौत गंदा पानी पीने से हो गई। इसमें लोगों की नहीं सरकार की गलती है, जो लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा पाई। अब भी कई लोग इसी वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन भाजपा अपनी गलती मानने की जगह मामले को किस तरह दबाने में लगी है, इसकी कई खबरें बाहर आ चुकी हैं ।मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है और इंदौर नगरनिगम पर भी भाजपा का ही कब्जा है। और इसके लिए भी भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी को ही श्रेय देते हैं। जैसे रविवार के कई अखबारों में मुंबई में जीत का श्रेय नरेन्द्र मोदी को देने वाले विज्ञापन एकनाथ शिंदे ने छपवाए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने भी मोदी के नेतृत्व को ही जीत का श्रेय दिया है। लेकिन क्या मोदी की भूमिका यहीं तक सीमित है कि वे भाजपा को किसी भी तरह से जीत दिलाएं और उसके बाद हारे हुए दलों पर नकारात्मक टिप्पणी करें। क्यों नरेन्द्र मोदी को अब तक फुर्सत नहीं मिली कि वे एक बार कुछ घंटों के लिए ही इंदौर चले जाते। वहां भी राहुल गांधी ही पहुंचे ।राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर लिखा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल। पानी में जहर, हवा में जहर, दवा में जहर, जमीन में जहर, और, जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर! कुछ इस तरह इस मॉडल में गरीबों की मौतों के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। सरकार अभी उनकी लापरवाही से हुई इंदौर की त्रासदी की जवाबदेही ले– दोषियों को सजा और पीड़ितों को अच्छा इलाज और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाए ।बता दें कि राहुल गांधी के इंदौर आने पर भी भाजपा विरोध कर रही थी। उसके मुताबिक राहुल गांधी राजनीति के मकसद से आ रहे थे। हालांकि इसे भाजपा की नासमझी ही माना जाए, क्योंकि राजनेता अगर राजनीति न करे तो फिर क्या करे। और अगर पीड़ितों के हक में आवाज उठाना या उनके आंसू पोंछने आना राजनीति है।

रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता जाल

राम सरन

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है ।देश की बढ़ती खाद्य माँग को पूरा करने के उद्देश्य से पिछले कई दशकों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग निरंतर बढ़ाया गया है ।शुरुआती दौर में इन उर्वरकों ने उत्पादन बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद की, लेकिन आज इनके अंधाधुंध और अनियंत्रित उपयोग के कारण कृषि, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर संकट मंडराने लगा है। उर्वरकों की खपत के भयावह आंकड़े देश में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2018–2019 में जहाँ 115 करोड़ बैग की खपत हुई थी, वहीं 2024–25 के दौरान यह आंकड़ा 150 करोड़ बैग को पार कर गया है ।गौर करने वाली बात यह है कि भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ है, जबकि उर्वरकों की खपत 150 करोड़ बैग से भी अधिक हो चुकी है ।यह असंतुलन न केवल चिंताजनक है, बल्कि भविष्य के लिए एक बड़े खतरे का संकेत भी है। सेहत और मिट्टी पर दोहरी मार रासायनिक उर्वरकों का असर अब हमारे थाल तक पहुँच चुका है ।गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ, फल और यहाँ तक कि दूध, दही और घी भी इनके रसायनों से अछूते नहीं रहे हैं ।इसके परिणामस्वरूप देश में कैंसर, हृदय घात, एलर्जी और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के मामले दिन–प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। खेतों की स्थिति भी कम सोचनीय नहीं है ।नियमानुसार, उर्वरकों का उपयोग केवल पौधों की जड़ों के पास होना चाहिए, लेकिन पूरे खेत में इनके छिड़काव से खरपतवार की समस्या बढ़ जाती है ।इस खरपतवार को खत्म करने के लिए फिर भारी मात्रा में खरपतवार–नाशक दवाओं का उपयोग होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देती हैं ।मिट्टी की खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए किसान और अधिक खाद डालता है, और यह दुष्चक्र हर साल मिट्टी को और अधिक बंजर बनाता जा रहा है। उर्वरक क्षेत्र में बढ़ता निवेश देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ रहा है ।वर्तमान में देश में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपये (सब्सिडी सहित) के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हो रहा है ।विडंबना यह है कि हमारा उर्वरक उद्योग 80 प्रतिशत तक विदेशी कच्चे माल या आयातित उर्वरकों पर निर्भर है ।कुल 3 लाख करोड़ रुपये में से 2.5 लाख करोड़ रुपये केवल आयात में खर्च हो जाते हैं ।इस प्रकार, एक ओर हमारी भूमि बंजर हो रही है, तो दूसरी ओर देश की बड़ी पूंजी विदेशों में जा रही है। सरकार किसानों के कल्याण के लिए भारी सब्सिडी दे रही है ।पिछले 10 वर्षों में लगभग 13 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की गई है ।इसी सब्सिडी के कारण 40 रुपये प्रति किलो वाली यूरिया खाद किसानों को 6 रुपये प्रति किलो से भी कम दाम पर उपलब्ध है ।स्थिति यह है कि यूरिया आज पशुओं के चारे से भी सस्ता हो गया है ।सरकार 85 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है ताकि किसानों को यूरिया एक चाय के कप से भी कम कीमत पर मिले ।लेकिन इसी कम कीमत का लाभ उठाकर बिचौलिए इसकी कालाबाजारी करते हैं और कृषि के बजाय इसका उपयोग प्लाईवुड कारखानों, कैटल फीड और मिलावटी दूध बनाने में कर रहे हैं। इस संकट से उबरने के लिए अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ।पहले खेतों से निकलने वाले अवशेषों का उपयोग जैविक खाद के रूप में होता था, जिससे मिट्टी का श्जैविक कार्बनश बना रहता था ।आज इन अवशेषों को बेचने से किसानों को कुछ लाभ तो होता है, लेकिन वह रासायनिक उर्वरकों की वास्तविक लागत के मुकाबले बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि वह रासायनिक उर्वरकों के बैग का वजन कम कर उसकी जगह जैविक खाद के विकल्प उपलब्ध कराए ।साथ ही, अत्यधिक उर्वरक उपयोग वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां विशेष निगरानी दल गठित किए जाने चाहिए। 1. हरी खाद का अधिक इस्तेमालरू जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग आवश्यक है, उसी तरह से मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए हरी खाद अनिवार्य है। 2. पौधों का विकासरू जैविक खाद के प्रयोग से पौधों की जड़ों को फैलने और गहराई तक जाने का पर्याप्त अवसर मिलता है।

सीनियर और युवा नेताओं के बीच संतुलन स्थापित करना नितिन नबीन के लिए होगी बड़ी चुनौती

संतोष

भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख जारी हो गई है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी बनाए गए डॉ के.लक्ष्मण ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। संगठन पर्व – 2024 के तहत जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, पार्टी ने शुक्रवार को ही निर्वाचक मंडल सूची का प्रकाशन कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू हो जाएगी। 19 जनवरी को ही दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। इसी दिन शाम को 4 से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। शाम 5 से 6 बजे तक नाम वापस लिया जा सकता है। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए एक से अधिक नेता नामांकन भरेंगे तो 20 जनवरी को चुनाव करवाया जाएगा। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए बीजेपी में कभी भी चुनाव की नौबत नहीं आई है। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि 20 जनवरी को सर्वसम्मति से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के चुने जाने का ऐलान कर दिया जाएगा। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नबीन के पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के साथ ही पार्टी में नए और बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। नितिन नबीन बीजेपी के न केवल सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे बल्कि वह पार्टी के पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिनका जन्म पार्टी की स्थापना के बाद हुआ है। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी जबकि नितिन नबीन का जन्म इसके 47 दिन बाद 23 मई 1980 को हुआ था। ऐसे में अब बीजेपी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करने की भी है कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी सिर्फ प्रतीकात्मक बदलाव का पर्याय भर बन कर न रह जाए। वहीं नई बीजेपी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका दिया जाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार से आने वाले इन युवा नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी टीम का गठन करना होगा। पार्टी संविधान के मुताबिक, पार्टी में सर्वोच्च फैसला लेने वाली इकाई पार्टी का संसदीय बोर्ड है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति का नंबर आता है जो चुनाव के समय उम्मीदवारों का चयन करता है। फिलहाल संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जेपी नड्डा है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद नितिन नबीन ही पार्टी का फैसला लेने वाले इस सर्वोच्च इकाई के अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बी एस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के.लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव और सत्यनारायण जटिया संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष संसदीय बोर्ड के सचिव के तौर पर इसमें शामिल हैं। इनमें से बीएल संतोष को छोड़कर बाकी सभी नेता 60 से ज्यादा उम्र के हैं। संसदीय बोर्ड के ये सारे सदस्य पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य हैं। संसदीय बोर्ड में शामिल इन 11 नेताओं के अलावा भूपेन्द्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, और वनथी श्रीनिवासन केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल हैं। सरकार के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नबीन की अध्यक्षता वाले पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति दोनों में ही शामिल रहेंगे। वहीं सरकार और पार्टी के अहम नेता के तौर पर अमित शाह भी इन दोनों समितियों का हिस्सा रहेंगे। लेकिन युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने के लक्ष्य और नई बीजेपी के गठन के लिए कई दिग्गज नेताओं को इससे बाहर जाना ही पड़ेगा। इन दोनों समितियों का पुनर्गठन करने के बाद पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को अपनी राष्ट्रीय टीम – यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्षों, राष्ट्रीय महासचिवों, राष्ट्रीय सचिवों और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ–साथ विभिन्न मोर्चों , समितियों और विभागों के मुखियाओं की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी। यह बात तो साफ है कि ये सारे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सहमति से ही लिए जाएंगे। हालांकि राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे नेताओं के बारे में अंतिम फैसला करने से पहले संघ से भी चर्चा की जाएगी। पार्टी की राष्ट्रीय टीम में ऐसे कई अन्य नेता भी शामिल हैं जो अपने–अपने राज्यों के मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं और इसलिए उन्हें हटाने से पहले कई समीकरणों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसे में यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि नितिन नबीन इन तमाम चुनौतियों से निपटते हुए अपनी नई टीम कैसे तैयार कर पाते हैं और कैसे तमाम उम्र के नेताओं यानी सीनियर एवं युवा के बीच संतुलन बना पाने में कामयाब हो पाते हैं।

राज्य चुनावों से पहले ईडी के फिर अति सक्रिय होने पर रहस्य गहराया

डॉ. ज्ञान

यह सही समय है कि सर्वोच्च न्यायालय को ईडी की कार्रवाई के साथ–साथ पूरे राजनीतिक पृष्ठभूमि और सत्ताधारी दल द्वारा जांच एजेंसी के संभावित दुरुपयोग पर भी विचार करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनावों के दौरान समान अवसर के लिए कुछ दिशानिर्देश होने चाहिए, और सत्ताधारी दल को तथाकथित कानूनी कार्रवाई के माध्यम से विपक्षी राजनीतिक अभियानों को पटरी से उतारने और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने से रोका जाना चाहिएभारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विपक्षी नेताओं और प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े हाई–प्रोफाइल राजनीतिक–कानूनी मामलों की सुनवाई कोई नई बात नहीं है। हालांकि, 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई की, उसका अप्रैल–मई 2026 में होने वाले पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनावों से पहले खास महत्व है। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ काम करने वाली राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर छापे के दौरान चोरी और रुकावट डालने का आरोप लगाया है ।यह एक खुला रहस्य है कि ईडी राष्ट्रीय और राज्य चुनावों से पहले अति सक्रिय हो जाती है और विपक्षी नेताओं के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू कर देती है, उन्हें नोटिस भेजती है, उन्हें अपने समक्ष पेश होने के लिए कहती है, उनके ठिकानों पर छापे मारती है, और यहां तक कि उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्त भी जब्त कर लेती है, जिससे विपक्षी पार्टियां कमजोर हो जाती हैं, उनके राजनीतिक अभियान पटरी से उतर जाते हैं और सीटों के मामले में उनके राजनीतिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह सत्ताधारी भाजपा और एनडीए को सत्ता हथियाने और विपक्ष को आसानी से हराने में मदद करता है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईडी पर कई बार प्रतिकूल टिप्पणी की है और कहा है कि यह केंद्र सरकार के एक उपकरण के रूप में काम नहीं कर सकता। यह सवाल अभी तक तय नहीं हुआ है कि क्या ईडी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी व्यवस्था के राजनीतिक हथियार के रूप में काम करता है? पूरा विपक्ष तो ऐसा ही आरोप लगाता है, और अनेक लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने केन्द्रीय अपराध अन्वेषण विभागों को विपक्षी नेताओं के पीछे लगा रखा है ।पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु उन पांच राज्यों में से हैं जहां अप्रैल–मई 2026 में चुनाव होने हैं, और हम देख रहे हैं कि ईडी कितनी सक्रिय हो गई है। दोनों राज्यों से विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कई कार्रवाइयों की खबरें आ रही हैं। 8 जनवरी को ईडी ने सॉल्ट लेक में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और इसके निदेशक प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास पर एक पुराने कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में छापा मारा था। चूंकि आईपैक टीएमसी के लिए काम करती है, इसलिए यह साफ है कि पार्टी का संवेदनशील राजनीतिक डेटा उनके पास है, जो ममता बनर्जी के लिए लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा राज्य में टीएमसी से सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है, और प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री ने बार–बार कहा है कि पश्चिम बंगाल उनका टॉप टारगेट है। इसलिए ईडी की कार्रवाई राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। ईडी के इस आरोप पर है कि आईपैक ऑफिस और उसके डायरेक्टर के ठिकानों पर छापे के दौरान उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रुकावट का सामना करना पड़ा, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र और विपुल पंचोली की सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने इसे श्बहुत गंभीरश बताया, और कहा कि वे नोटिस जारी करके मामले की जांच करेंगे। उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी की, श्यह बहुत गंभीर मामला हैय हम नोटिस जारी करेंगे। हमें इसकी जांच करनी होगी ।श्इस मामले पर 9 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट में भी हंगामा हुआ था, जिस पर बेंच ने कहा कि ईडी छापे मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट में हुए हंगामे से वे बहुत परेशान हैं। गौरतलब है कि हंगामे के बाद, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोर्टरूम के अंदर बेकाबू अराजकता का हवाला देते हुए, राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर ईडी के तलाशी और जब्ती अभियान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। जांच एजेंसी के छापे के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार का श्हस्तक्षेप और रुकावटश एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है, ईडी की ओर से पेश हुए सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा। उन्होंने कहा कि इससे दूसरों को बढ़ावा मिलेगा और केंद्रीय बलों का मनोबल गिरेगा तथा श्राज्यों को लगेगा कि वे छापामारी के दौरान घुस सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, और फिर धरने पर बैठ सकते हैं। एक मिसाल कायम की जानी चाहिए, जो अधिकारी वहां मौजूद थे, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए ।श कलकत्ता हाईकोर्ट में हुए हंगामे के बारे में, श्री मेहता ने कहा कि सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में वकील और अन्य लोग कोर्ट में घुस गए, जिसके कारण सुनवाई स्थगित करना पड़ी, और कहा, श्ऐसा तब होता है जब लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र ले लेता है ।श्वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ईडी की याचिका का विरोध किया और कहा कि मामले की सुनवाई पहले हाईकोर्ट में होनी चाहिए। उन्होंने कहा, श्यह सरासर झूठ है कि सभी डिजिटल डिवाइस ले लिए गए। यह आरोप कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी डिवाइस ले लिए, झूठ है, जिसकी पुष्टि ईडी के अपने पंचनामे (तलाशी रिकॉर्ड) से होती है ।श उन्होंने यह भी कहा, श्कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया थाय तब से ईडी क्या कर रही थी? चुनावों के बीच इतनी जल्दबाजी क्यों?श हालांकि ईडी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परिसर में घुसीं और जांच से जुड़े श्अहमश सबूत ले गईं, ममता ने केंद्रीय एजेंसी पर अपनी हद पार करने का आरोप लगाया है, और पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ममता की तरफ से पेश होते हुए श्री सिब्बल ने कहा, श्हम सब जानते हैं कि आईपैक पश्चिम बंगाल में चुनावों का काम देखती है। आईपैक और टीएमसी के बीच एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। उन्होंने आगे कहा, श्चुनाव का डेटा गुप्त होता है और वह सब वहीं रखा जाता है। उम्मीदवारों वगैरह के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। एक बार जब आपके पास जानकारी आ जाएगी, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? ममता बनर्जी को विरोध करने का अधिकार है कि वह इसकी रक्षा करें और इसलिए वे वहां गयीं ।श इस पूरे मामले को सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं माना जा सकता। ईडी की कार्रवाई हमेशा पूरी तरह से प्रशासनिक नहीं होती, खासकर चुनावों से पहले या उसके दौरान उनकी अति सक्रिय भूमिका को देखते हुए, और वह भी मुख्य रूप से विपक्षी नेताओं के खिलाफ। 2014 से, 95 प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, जबकि जुलाई 2025 तक भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ 0.1 प्रतिशत दोषसिद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि ईडी के पास विपक्षी नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं होते हैं। आम चुनाव 2024 से पहले भी, कई नेताओं को ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसमें आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झामुमो नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल हैं। सरकार का रुख है कि वे श्भ्रष्टों के झुंडश (जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं और इंडिया गठबंधन को कहा है) के खिलाफ कार्रवाई करने पर तुले हुए हैं। कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि राजनीतिक पद कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं देता, भले ही गिरफ्तारियां चुनावों के करीब हों, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है।

मोदी ओवैसी का हिन्दू मुस्लिम खेल धर्मनिरपेक्ष दलों को खत्म करने के लिए

शकील

अख्तरराजनीति इस राजनीति को ओवैसी नहीं रोक पाएंगे। इसे देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस ही रोक पाएगा और कांग्रेस कभी भी किसी एक धर्म की जाति की पार्टी नहीं हो सकती। आजादी के आंदोलन से निकली पार्टी है उसे चाहे जितना संघर्ष करना पड़े वह जात–पात से ऊपर उठी पार्टी ही बनी रहेगी। जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं डीएनए, वह ही ऐसा है कि कोई चाहे तो भी पार्टी का स्वभाव बदल नहीं सकता। बिहार विधानसभा के बाद महाराष्ट्र स्थानीय निकायों के चुनाव खतरे की आखिरी घंटी है। अगर मुस्लिम नहीं समझे तो बंगाल में जिसे वे अपना कायद (नेता) मान रहे हैं उन ओवैसी की सरकार तो नहीं बन पाएगी मगर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार जरूर खतरे में पड़ जाएगी और बीजेपी की सीटें वहां बढ़ जाएंगी। बिहार में भी बढ़ीं महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनावों में भी बढ़ीं। और दोनों जगह नुकसान धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का हुआ ।देश में धर्मनिरपेक्ष राजनीति की जरूरत हिन्दू को भी है मुस्लिम को भी। मगर किसी भी देश में वह अल्पसंख्यक को ज्यादा होती है। भारत में मुस्लिम को ज्यादा है। बांग्लादेश में हिन्दू को। पाकिस्तान में जो मुस्लिम–हिन्दू राजनीति वजह से बरबाद हो गया वहां दोनों को। क्योंकि एक हद के बाहर यह धर्म की राजनीति दोनों को मारने लगती है और फिर बहुसंख्यक को ज्यादा। पाकिस्तान में यही होने लगा है। अल्पसंख्यक को जितना नुकसान होना था हो चुका है। अब बहुसंख्यक मुस्लिम ही मजहब की राजनीति का नुकसान उठा रहा है। तरक्की की दौड़ में पिछड़ कर ।पाकिस्तान जैसी स्थिति से बचने के लिए हिन्दुओं का बड़ा वर्ग सचेत है। प्रधानमंत्री मोदी का वोट 37 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसे पचास से ऊपर ले जाने के लिए उन्हें हिन्दुओं को और उग्र करने की जरूरत है। जो वे अपने तमाम शमशान, कब्रिस्तान, होली, दीवाली, ईद, मंगल सूत्र छीन लेंगे, यहां तक कि लड़की उठा ले जाएंगे जैसे भाषणों के बाद भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके लिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है। मुस्लिमों के ध्रुवीकरण का। मुस्लिम अगर एक झंडे के नीचे दिखेंगे तो हिन्दुओं को यह बताने में आसानी होगी कि देखो वे एक साथ हैं तुम भी एक साथ आओ ।अपने दम पर भीड़ इकठ्ठी करने की एक सीमा होती है। मोदी उस सीमा तक पहुंच चुके हैं। अब उससे आगे लोगों को इकठ्ठा करने के लिए उन्हें डर दिखाने की जरूरत है। वह देखो सब ओवैसी के साथ जा रहे हैं। तुम मेरे साथ आओ। हिन्दू राजनीति मुस्लिम राजनीति। धर्मनिरपेक्ष दलों को खत्म करने की साजिश। बीजेपी हिन्दू पार्टी बन सकती है। बन ही गई है। केन्द्र सरकार से जो एक दो थे वे मुस्लिम मंत्री हटा दिए हैं। लोकसभा विधानसभाओं में टिकट देना बंद कर दिए हैं। उनके कई बड़े नेता मंत्री कहने लगे हैं कि हमें मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए। अब तो यहां तक भी कहा जाने लगा है कि अपने काम के लिए भी हमारे पास नहीं आएं। कहने वाले मंत्री विधायक सांसद हैं। जो संविधान की या अपनी धार्मिक आस्था की शपथ लिए हुए हैं कि वे बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे ।इस राजनीति को ओवैसी नहीं रोक पाएंगे। इसे देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस ही रोक पाएगा और कांग्रेस कभी भी किसी एक धर्म की जाति की पार्टी नहीं हो सकती। आजादी के आंदोलन से निकली पार्टी है उसे चाहे जितना संघर्ष करना पड़े वह जात–पात से ऊपर उठी पार्टी ही बनी रहेगी। जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं डीएनए, वह ही ऐसा है कि कोई चाहे तो भी पार्टी का स्वभाव बदल नहीं सकता। मोदी को सबसे ज्यादा परेशानी ही कांग्रेस से है। प्रधानमंत्री बनते ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। एआईएमआईएम मुक्त भारत का क्यों नहीं? यह ओवैसी की पार्टी है। जिसका नाम ही है मुस्लिम एकता की पार्टी। आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमिन (एआईएमआईएम)। विरोध तो मुस्लिम का करते हैं। एक हजार साल पहले के इतिहास में जाकर कहते हैं कि आज भी वे लोग मौजूद हैं। और उनके सुरक्षा सलाहकार डोभाल तो बदला लेने की बात कहते हैं। मगर मुस्लिम पार्टी को बढ़ावा देते हैं। उसके अध्यक्ष ओवैसी को विदेशों में भेजते हैं भारत का पक्ष रखने के लिए। सब साफ दीवार पर मोटे–मोटे हर्फों (अक्षरों) में लिखा दिख रहा है मगर मुस्लिमों के एक बड़े हिस्से के आंखों पर भी पट्टी बंध गई है जो यह नहीं देख पा रहा कि मोदी और ओवैसी दोनों की राजनीति एक है। एक हिन्दू की करेगा एक मुस्लिम की। धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को खत्म करने की कोशिश ।यह व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, विचारों की है। धर्मनिपरपेक्षता को खत्म करने के लिए पहले ही छद्म धर्मनिरपेक्षता शब्द गढ़ लिया गया था। जात–पात से ऊपर उठकर सबकी बात करने वालों को छद्म धर्मनिरपेक्ष के साथ अपीजमेंट (तुष्टिकरण) करने वाला कहा गया। मगर देश के हिन्दू और मुस्लिम दोनों ने बीजेपी की इस राजनीति को लंबे समय तक रोके रखा। लेकिन आज मोदी की धार्मिक विभाजन की राजनीति हिन्दू के साथ मुस्लिम भी फंसा दिखता है। अगर मोदी और ओवैसी की यह राजनीति सफल हो गई तो देश को पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मुस्लिम के साथ हिन्दू की और हिन्दू के साथ मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि एक मोदी के जाल से निकले और दूसरा ओवैसी के जाल से। वैसे तो असल में दोनों एक ही हैं। हिन्दू राजनीति मुस्लिम राजनीति को फायदा पहुंचाती है और मुस्लिम राजनीति हिन्दू राजनीति को। और दोनों मिलकर देश को नुकसान पहुंचाते हैं ।ऐसे ही द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत सावरकर ने शुरू किया था। समझिए इसीलिए बीजेपी उनके तमाम धार्मिक विचार जो गाय को लेकर भी हैं से अनकम्फर्टेबल रहकर भी उन्हें अपना आदर्श मानती है। बाद में जिन्ना ने भी इस विचार को अपना लिया। और इसका नतीजा देश ने हिन्दू–मुस्लिम राजनीति के रूप में देखा। लेकिन उस समय गांधी थे, नेहरू थे जिनके विशाल व्यक्तित्व ने नफरत और विभाजन की राजनीति के बावजूद देश को संभाले रखा। गांधी को तो अपना बलिदान देना पड़ा। और बाद में नेहरु ने भारत को इस नफरत की राजनीति से बहुत मेहनत और समझ से बाहर निकाला। देश का नवनिर्माण किया। नेहरू का आज तक विरोध करने का यही कारण है। कि वे धर्मनिरपेक्षता, तरक्की और वैज्ञानिक मिजाज की बात करते थे। मोदी तो नेहरू का विरोध करते ही हैं ओवैसी भी करते हैं। वे तो और आगे बढ़कर राहुल की नकल उतारते हुए यह बताते हैं कि वे क्या बोलते, करते हैं। बहुत ही वाहियात मिमिक्री। क्या बोलते हैं राहुल? आज तक किसी भी समुदाय के बारे में कोई गलत बात बोली? हमेशा यही बोला कि मैं सबके साथ खड़ा हूं। हिन्दू–मुस्लिम सबके। क्या चाहते हैं ओवैसी कि राहुल किसी एक समुदाय के साथ खड़े हो जाएं! मोदी भी यही चाहते हैं। दोनों की राजनीति आसान हो जाएगी। लेकिन ओवैसी जरा यह बता दें कि केवल मुस्लिम के वोट से वे हिजाबी प्रधानमंत्री कैसे बना लेंगे? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबको नुकसान पहुंचाकर उनका बड़ा अचीवमेंट क्या है? खुद की जीती सीटें या बीजेपी को मुंबई में रिकार्ड जिताई 89 सीटें? 13 नगर निगमों में उनकी जीत 125 वार्डों में बताई जा रही है। और इससे कई गुना ज्यादा सीटों पर उन्होंने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के उम्मीदवारों को हराया है। यही उन्हें काम दिया गया था और यही उनकी उपलब्धि है। खुद कहीं अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे। मगर बीजेपी के बनवा देंगे ।अब कुछ ही समय में बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ओवैसी गोदी मीडिया के बाद सबसे बड़े मोदी समर्थक के रूप में नजर आएंगे। वैसी ही घोषणा करते हुए जैसा गोदी मीडिया कहता है कि हम मोदी के साथ थोड़ी हैं। गोदी मीडिया तो पूरी तरह एक्सपोज हो गया। जनता समझने लगी है कि वह केवल मोदी के लिए ही काम करता है। ओवैसी के बारे में मुस्लिम के लिए यह समझना अभी बाकी है।

छुट्टी के दिन नहीं कटेगी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की बिजली, निदेशक ने जारी की एसओपी

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की मनमाने तरीके से बिजली काटने पर अंकुश लगाया है। ऐसे उपभोक्ताओं की अब छुट्टी के दिन ऑटोमैटिक बिजली काटी नहीं जाएगी। इस संबंध में कॉर्पोरेशन के निदेशक (वाणिज्यराजधानी लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की मनमाने तरीके से बिजली काटने पर अंकुश लगाया है।) एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी किया है। एसओपी में प्रीपेड मीटर धारक बिजली उपभोक्ताओं को अन्य बहुत सी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। निदेशक प्रशांत वर्मा ने 16 जनवरी को जारी किए एसओपी के सरकुलर में मध्यांचल व अन्य विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को आदेश दिया कि इसको सख्ती से लागू कराया जाए। इस आदेश से राजधानी लखनऊ में डेढ़ लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं को राहत हासिल होगी। एसओपी में बकायेदार की बिजली शाम छह से आठ बजे के बीच और प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार व प्रत्येक रविवार को भी बत्ती काटने पर पाबंदी का प्रावधान किया गया है। निदेशक ने यह भी आदेश दिया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को तीन दिन का इमरजेंसी क्रेडिट (बैलेंस खत्म होने पर भी बत्ती नहीं कटेगी) देने का निर्णय लिया है। यूं समझे, किसी उपभोक्ता का बैलेंस 25 जनवरी को खत्म हो जाता, तो उसकी बिजली 28 जनवरी तक नहीं कटेगी। यहीं नहीं, तीन दिन के बाद सार्वजनिक अवकाश द्वितीय शनिवार, रविवार के साथ ही राष्ट्रीय अवकाश पड़ जाता तो भी बत्ती नहीं काटी जाएगी। उपभोक्ता अवकाश के बाद कार्य दिवस में मीटर को रिचार्ज न करें तो बिजली काटी जा सकती। एसओपी में यह भी प्रावधान किया गया, कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जो उपभोक्ता बैलेंस खत्म होने पर रिचार्ज नहीं कर रहे तो उनकी बिजली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक ही काटी जाएगी। इससे बकायेदार को प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करने और एजेंसी को कनेक्शन को जोड़ने में सहूलियत रहेगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की मॉनीटरिंग करने वाली एजेंसियों के लिए प्रत्येक विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अवकाश की सूची जारी करेंगे, जिससे बिजली काटने की मनमानी पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही, एजेंसियों के जिम्मेदारों के साथ बैठक करके इस एसओपी पर अमल कराया जाए। उपभोक्ता का मीटर प्रीपेड होने से पहले 10 हजार रुपये का बिल बकाया था। वह 2000 रुपये का रिचार्ज कराएगा तो 1000 रुपये पुराने बकाये में समायोजित हो जाएंगे। इससे 1000 रुपये का ही बैलेंस रहेगा। यह क्रम तब तक चलेगा, जब तक बकाया शून्य नहीं हो जाएगा। शहर के कई इलाकों में सोमवार को मेंटेनेंस के चलते बिजली बंद रहेगी। अमीनाबाद न्यू पावर हाउस के आईसीआईसीआई बैंक, लाटूश रोड, न्यू मेडिसिन मार्केट, धोबी वाली गली, कैसरबाग खटिकाना, कैसरबाग मछली मंडी, सब्जी मंडी, लाल मस्जिद, ओल्ड मेडिसिन मार्केट की बिजली दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी।

निजी स्कूलों में आरटीई से प्रवेश के लिए शासन का आदेश जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश लिए आवेदन 2 फरवरी से शुरू होंगे। इसके लिए सोमवार को तीन चरणों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार दो माह देरी से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष 1 दिसंबर से ही आवेदन शुरू हो गए थे। चार चरण में आवेदन लिए गए थे। इस बारे में राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से सभी जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए

आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के अलावा द्विव्यांग प्रमाण पत्र (जिसके लिए लागू हो) जैसे दस्तावेज लगेंगे। तीन चरणों में इस तरह पूरी होगी प्रवेश प्रक्रिया पहले चरण में आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगी। आवेदन के साथ सत्यापन भी होगा। इसके लिए 18 फरवरी को लाटरी निकाली जाएगी। 20 फरवरी को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। दूसरे चरण में आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे। लाटरी 9 मार्च को निकलेगी। 11 मार्च को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। तीसरे चरण के आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक लिए जाएंगे। लाटरी 27 मार्च को निकलेगी। 29 मार्च को स्कूल आवंटित किया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

प्रदेश के 13 जिलों के अभ्यार्थियों के लिए शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली

लखनऊ, (संवाददाता)। छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर (एएमसी) स्टेडियम में 6 फरवरी से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा, जो 20 फरवरी तक चलेगी। इस रैली में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के करीब 13000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। ये सभी अभ्यर्थी जुलाई 2023 में आयोजित लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि एएमसी स्टेडियम में अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी), अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्कध्स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन श्रेणियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों को रात दो बजे तक एएमसी सेंटर एवं कॉलेज स्टेडियम में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। यह भर्ती रैली उत्तर प्रदेश की छठी अग्निवीर रैली होगी। आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, लखनऊ के अंतर्गत आने वाले 13 जिलों के शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ई–मेल आईडी पर अलग–अलग एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के दलालों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस रैली में औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ जिलों के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे।

राष्ट्र सेवा में सतत सक्रिय हों युवा

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर के कौशलपुरी में रविवार को आयोजित हिंदू सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संपर्क प्रमुख मनोज ने कहा कि समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए संगठनात्मक एकता, सांस्कृतिक चेतना और समरसता आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रसेवा के लिए सतत सक्रिय रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस महाराज और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रजनी पांडेय भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सभी ने राष्ट्रहित और समाजसेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर रितु शाही, ज्योति, अशोक तिवारी, अनिल, अमरीश, हृदय नारायण, अंगद, विजय, मनीष तिवारी, हरीश, राकेश, डॉ. संतोष शुक्ला, घनश्याम, धनंजय, सुभाष चंद तिवारी आदि मौजूद रहे।

सत्संग से मिलती है सही दिशा

लखनऊ, (संवाददाता)। वृंदावन योजना कॉलोनी सेक्टर–6बी में रविवार को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से भंजन एवं सत्संग हुआ। कथावाचक शालिनी भारती ने सत्संग का महत्व समझाया। कहा कि जीवन की भागदौड़ में अक्सर मनुष्य बुद्धि का तो विस्तार करता है लेकिन विवेक के अभाव में विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। वैज्ञानिक प्रगति की दौड़ में हम ब्रह्मांड की गहराइयों को नाप रहे हैं लेकिन उस चेतना को नहीं जान पा रहे जो इस सृष्टि का आधार है। ऐसे समय में सत्संग वह प्रकाश स्तंभ बनकर उभरता है जो व्यक्ति को विवेक और भक्ति का मार्ग दिखाता है। इससे जीवन को सही दिशा मिलती है।

प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन-3 में आगे कार्यवाही पर दो फरवरी तक बढ़ी रोक

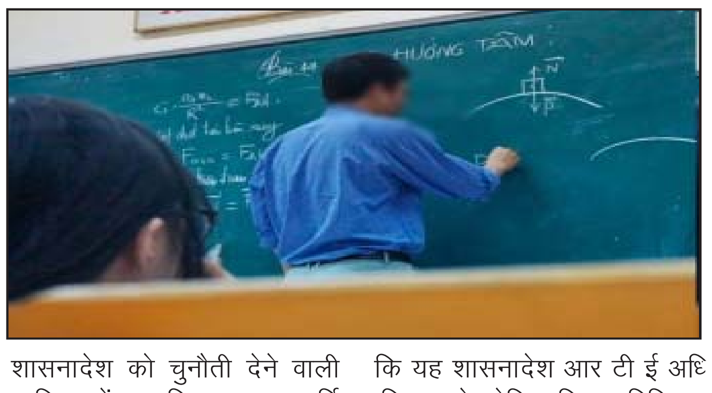

लखनऊ, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन –3 मामले में आगे किसी कार्यवाही पर 19 जनवरी तक लगी रोक, दो फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याची शिक्षकों की अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह परिहार ने बताया कि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो फरवरी को नियत करके अंतरिम आदेश दिया कि मामले की इस अगली सुनवाई की तिथि तक बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर, समायोजन –3 मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं करेंगें। कोर्ट ने कहा कि इस अंतरिम आदेश की राहत, इस याचिका के साथ संबद्ध अन्य याचिकाओं के याची शिक्षकों को भी उपलब्ध होगी। कोर्ट ने यह आदेश प्राथमिक शिक्षकों के समायोजनध स्थानांतरण – 3 के शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया। न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश बाराबंकी की संगीता पाल समेत 29 प्राथमिक शिक्षकों की याचिका पर दिया। याचिकाओं में 14 नवंबर 2025 के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षकों के समायोजनध स्थानांतरण के शासनादेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच जी एस परिहार का कहना था कि यह शासनादेश आर टी ई अधिनियम समेत बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के नियमों का उल्लंघन करने वाला है। इसके नियम 21 के तहत शिक्षक की सहमति के बाहर समायोजित न किए जाने की दलील दी। कहा इस समायोजन से जहां शिक्षकों की वरिष्ठता पर असर पड़ रहा है, वहीं निर्धारित छात्र– शिक्षक अनुपात प्रभावित होने जैसी अन्य विसंगतियां भी पैदा हो रही हैं। उधर, मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पेश हुए।

वोटर लिस्ट है या पहेली, वर्षों पुराने मतदाताओं को थमाए जा रहे नोटिस

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्तियों और शिकायतों का अंबार लग रहा है। रविवार को लखनऊ के विभिन्न बूथों पर मतदाता सूची पढ़कर सुनाने के बाद ऐसी लापरवाही सामने आई है, जहां वर्षों से वोट डाल रहे बुजुर्गों से अजीबोगरीब जानकारियां मांगी गईं, तो कहीं एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के नाम सूची से नदारद मिले। मकबूलगंज की नेहा जायसवाल ने बताया कि उनकी 64 वर्षीय मां पुष्पा जायसवाल 25 वर्षों से वोट डाल रही हैं। इसके बावजूद बीएलओ ने उन्हें नोटिस देकर उनके मायके की जानकारी मांगी है। फूलबाग की रहमीन के मुताबिक, उन्होंने अपनी तीन बहनों के साथ फॉर्म भरा था, लेकिन सूची में उनकी मझली बहन यासमीन का नाम नहीं है। अब विभाग दोबारा फॉर्म भरवा रहा है। एमा थॉमस इंटर कॉलेज बूथ पर फरहत नाज ने बताया कि आवेदन पूर्ण होने के बावजूद बीएलओ ने फोन कर नोटिस थमाया और दोबारा फॉर्म भरवाया। इस्लामिया इंटर कॉलेज सहित जिले के अधिकांश बूथों पर सुबह सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर 12रू30 बजे तक बीएलओ मतदाताओं का इंतजार करते दिखे। हालांकि, दोपहर बाद धीरे–धीरे लोग बूथों पर पहुंचे। बीएलओ ने ड्राफ्ट सूची पढ़कर सुनाई और नए मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध कराए। किसी भी बूथ पर भारी भीड़ जैसी स्थिति नहीं देखी गई। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर सिंह ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन फॉर्मों में जानकारी अधूरी थी या जिनकी 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हो पाई थी, केवल उन्हीं को नोटिस जारी किए गए हैं। मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने पर किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी के मुताबिक, अभियान जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों के 4132 मतदान स्थलों पर बीएलओ ने रविवार को मतदाता सूची पढ़कर सुनाई। इस दौरान कुल 8,460 फॉर्म प्राप्त हुए। जिनमें फॉर्म–6 (नया नाम जोड़ने) के 1,665 और फॉर्म–8 (संशोधन) के 83 आवेदन शामिल हैं। मृतक, स्थानांतरित, अनुपस्थित या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाए गए हैं।

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली बागडोगरा इंडिगो फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

लखनऊ, (संवाददाता)। शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली कि इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या जो दिल्ली से बागडोगरा जा रही थी, में बम होने की धमकी प्राप्त हुई है। यह सूचना प्रातः लगभग 08रू46 बजे मिली, जिसके बाद सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करते हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई। फ्लाइट ने सुबह 09रू17 बजे सुरक्षित रूप से लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की और तत्पश्चात विमान को तत्काल आइसोलेशन बे में पार्क कराया गया।प्रारंभिक जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि धमकी से संबंधित एक हाथ से लिखा हुआ नोट टिशू पेपर पर मिला है, जिस पर "प्लेन में बम" लिखा हुआ था। उक्त फ्लाइट में कुल 222 यात्री और 8 शिशु सवार थे, जबकि विमान का संचालन 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई के चलते सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।घटना की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता, सुरक्षा एजेंसियां और एयरपोर्ट प्रशासन मौके पर पहुंच गया और विमान व आसपास के क्षेत्र की गहन सुरक्षा जांच शुरू की गई। पूरे घटनाक्रम पर पुलिस और संबंधित एजेंसियों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। मामले की विस्तृत जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रचलित है तथा धमकी से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून–व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है।

मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी बैनामा कर भूमि बेचने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश

लखनऊ, (संवाददाता)। एलईडी टीवी बरामदलखनऊ, । पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के दक्षिणी जोन अंतर्गत थाना मोहनलालगंज पुलिस ने मृत व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग कर फर्जी बैनामा के माध्यम से कृषि भूमि विक्रय करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि से खरीदा गया एक एसी और एक एलईडी टीवी भी बरामद किया गया है।थाना मोहनलालगंज में ग्राम उदयपुर निगोहा स्थित कृषि योग्य भूमि के संबंध में फर्जी बैनामा कराए जाने के आरोप में मुकदमा संख्या 562ध2024 अंतर्गत बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। वादिनी विमला सिंह द्वारा दी गई सूचना में बताया गया कि उनके स्वर्गीय पति अवधराज सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि को मृतक के नाम का दुरुपयोग करते हुए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बैनामा करा लिया गया है। जांच के दौरान राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि गाटा संख्या 296, रकबा 0.449 हेक्टेयर भूमि आशालता वर्मा और स्वर्गीय अवधराज सिंह के नाम सह–खातेदार के रूप में दर्ज थी, जबकि अवधराज सिंह की मृत्यु 16 फरवरी 2023 को हो चुकी थी। इसके बावजूद अभियुक्तों ने एक फर्जी व्यक्ति को मृतक अवधराज सिंह के रूप में प्रस्तुत कर भूमि का विक्रय कर दिया।विवेचना में यह स्पष्ट हुआ कि राजकुमार, ज्ञानेन्द्र राजपूत और सर्वेश द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक अज्ञात व्यक्ति को अवधराज सिंह के नाम से विक्रेता बनाकर प्रस्तुत किया गया।

जातीय रैलियों पर रोक को लेकर हाईकोर्ट सुना सकता है अहम फैसला

लखनऊ, (संवाददाता)। हाईकोर्ट की लखनउ पीठ में जातीय रैलियों पर रोक के मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ के समक्ष स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की वर्ष 2013 में दाखिल जनहित याचिका 19 जनवरी को सूचीबद्ध है।मामले की पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा था कि जातीय रैलियों को रोकने समेत अपराधिक मामलों में लोगों की जाति न लिखे जाने का आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत पुलिस महानिदेशक ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है।मामले में केंद्र सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र के जवाब पर याची को प्रतिउत्तर दाखिल करने का समय दिया था। पहले, इस मामले में कोर्ट ने प्रदेश में जातीय रैलियों पर रोक का अंतरिम आदेश जारी करके, पक्षकारों केंद्र व राज्य सरकार समेत केंद्रीय निर्वाचन आयोग एवं चार राजनीतिक दलों कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से जवाब मांगा था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ पीठ में सरकारी वकीलों की तैनाती प्रक्रिया को चुनौती मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ के समक्ष मामले में दाखिल चार जनहित याचिकाएं, 19 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।इस मामले में हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की तैनाती में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया गया है। साथ ही सरकारी वकीलों की तैनाती के 1975 के एल आर मैनुअल में भी संशोधन करने की गुजारिश भी की गई है। मामले में वर्ष 2017 में दाखिल महेंद्र सिंह पवार की जनहित याचिका समेत चार जनहित याचिकाओं में हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की तैनाती प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ पीठ में दो हजार से अधिक सरकारी वकील तैनात हैं।

संगठन सृजन अभियान को गति देने के लिए कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ की अहम बैठक

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ के नव नियुक्त चेयरमैन डॉ. अमित कुमार राय की अध्यक्षता में शिक्षक प्रकोष्ठ के पूर्व पदाधिकारियों एवं प्रदेश भर से आए शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। यह बैठक प्रदेश में चल रहे संगठन सृजन अभियान को गति देने और शिक्षक प्रकोष्ठ की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के उद्देश्य से आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय उपस्थित रहे।बैठक की औपचारिक शुरुआत शिक्षक प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ. अमित कुमार राय द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुष्पगुच्छ भेंट कर की गई। इसके बाद बैठक को संबोधित करते हुए अजय राय ने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं। शिक्षक अपने विचारों और चिंतन से राजनीति के पथ को दिशा दिखाते हैं और देश व समाज की दिशा तथा दशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश कांग्रेस का शिक्षक प्रकोष्ठ आने वाले समय में शिक्षकों की समस्याओं और मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर उतरकर व्यापक संघर्ष से भी पीछे नहीं हटेगा।अपने अध्यक्षीय संबोधन में कांग्रेस शिक्षक प्रकोष्ठ के नव नियुक्त चेयरमैन डॉ. अमित कुमार राय ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास उनमें जताया है, वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और विचारधारा को अधिक से अधिक शिक्षकों तक पहुंचाने के साथ–साथ वर्तमान समय में शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से उठाया जाएगा और उनके समाधान के लिए सभी के सहयोग से व्यापक आंदोलन किया जाएगा।डॉ. अमित राय ने कहा कि आने वाले 100 दिनों के भीतर प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों को संगठन से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा।

संघ के पंच परिवर्तनों को जन–जन तक पहुंचाएं

लखनऊ, (संवाददाता)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंच परिवर्तनों को जन–जन तक पहुंचाएं। इसके लिए हिंदू सम्मेलनों के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह आह्वान हिंदू सम्मेलन में दयानंदनगर के सरसंघचालक मनमोहन ने किया। रविवार को जुगौली रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित गेस्ट हाउस में दोपहर 12 बजे आयोजित हिंदू सम्मेलन में मनमोहन ने कहा कि यह समारोह हिंदुओं में पंच परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी व नागरिक कर्तव्य लाने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन पंच परिवर्तनों को जन–जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। वक्ता कुलदीप तिवारी ने कहा कि व्यक्ति को सम्मान उसके आचरण, संयम व कर्तव्य के अनुरूप मिलता है। भारत के लोकतंत्र में परिवर्तन हो रहा है, उसकी हम सबको चिंता करने की जरूरत है। वक्ता स्निग्धा चटखंडी व राधा ने पंच परिवर्तनों की व्याख्या की। कार्यक्रम आयोजक विजय कुमार निगम ने कहा कि विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करें। सम्मेलन में नगर कार्यवाहक दीपक, बौद्धिक प्रमुख दयाशंकर, गोमतीनगर वार्ड के पार्षद कौशल किशोर पांडेय ,भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, भाजपा के मंडल अध्यक्ष जय सिंह व जय करन सिंह, नितिन माथुर आदि की उपस्थित रही। शिवाजी मार्ग मॉडल हाउस में आयोजित हिंदू सम्मेलन में हनुमंत धाम के महंत रामसेवक दास महाराज ने कहा कि हिंदू जात–पात में न बंटे, संगठित रहें। एकजुटता से जो किसी भी नफरत से निपटा जा सकता है। इससे पूर्व हिंदू सम्मेलन का शुभारंभ सुबह 11 बजे गुरुकुल के बटुक वेद मित्रों के उच्चारण के साथ विधि विधान से हुआ। कार्यक्रम में श्रीमद्भागवत गीता का 15 अध्याय का पाठ किया गया।

मणिकर्णिका घाट पर तोड़-फोड़ को लेकर योगी सरकार पर कांग्रेस का तीखा हमला

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़–फोड़ और आस्था की प्रतीक माता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्तियों को तोड़कर मलबे में फेंक दिए जाने की घटना को बेहद संवेदनहीन और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए योगी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी भी मौजूद रहे। प्रेसवार्ता की शुरुआत माता अहिल्याबाई होल्कर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई।अजय राय ने कहा कि चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला रहा हो या फिर माता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्तियों को तोड़ने की घटना, काशी की पौराणिकता और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का कार्य कोई बाहरी ताकत नहीं कर रही, बल्कि यह दुखद सच्चाई है कि यह सब उन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है जो कभी कहते थे कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। आज वही लोग मां गंगा और काशी के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रहे हैं।उन्होंने कहा कि 25 मई 2025 को भाजपा माता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पूरे देश में भव्य आयोजनों के साथ मनाती है, चांदी के सिक्के जारी करती है और आस्था के नाम पर बड़े–बड़े इवेंट करती है, लेकिन ठीक छह महीने बाद उन्हीं माता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्तियों पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। अजय राय ने इसे भाजपा की दोहरी सोच और अवसरवादी राजनीति का जीता–जागता उदाहरण बताया।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि योगी सरकार अपनी गलती

स्वीकार करने के बजाय जनता और सच्चाई बोलने वालों को डराने के लिए एफआईआर का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सच्चाई से भली–भांति परिचित हैं, इसीलिए वाराणसी जाकर लीपापोती करने का प्रयास किया गया और यह दावा किया गया कि सामने आई तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं। अजय राय ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें नैतिक साहस है तो वे सभी पत्रकारों को उस स्थान पर ले जाकर यह स्पष्ट करें कि माता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्तियां नहीं तोड़ी गईं।अजय राय ने कहा कि भाजपा का असली चरित्र आस्था नहीं बल्कि व्यापार है। यह लोग भावनाओं में नहीं बल्कि इवेंट में विश्वास रखते हैं। कभी राम के नाम पर, कभी शिव के नाम पर और कभी माता अहिल्याबाई के नाम पर जनता की आस्था को व्यापार में बदला जाता है। उन्होंने कहा कि प्रभु राम के नाम पर बने ट्रस्ट में हुए कथित घोटाले, राम पथ में एक वर्ष के भीतर पड़ी दरारें, मंदिर में पानी टपकने की घटनाएं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर प्राचीन शिवलिंगों को तोड़े जाने की बातें किसी से छिपी नहीं हैं और आज उसी सिलसिले को माता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्तियों के साथ दोहराया जा रहा है।

जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देना गलत : अजय राय

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जौनपुर पहुंचे, उन्होंने प्रयागराज में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ मेला प्रशासन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और शंकराचार्य की उपाधि को लेकर उनको दिए गए नोटिस पर अजय राय ने कहा कि माघ मेला प्रसाशन द्वारा किया गया व्यवहार बेहद ही निंदनीय है, क्या जिला प्रशासन अब उनको शंकराचार्य की उपाधि देगा या योगी और मोदी लोगों को शंकराचार्य बनाएंगे जो खुद संत नहीं है।प्रयागराज में जब वह महाकुंभ में आए थे तो उन्होंने जमीन

आवंटित किस आधार पर की गई थी,उस समय यह सब सवाल क्यों नहीं उठाया गया। प्रत्येक व्यक्ति उनको अपना शंकराचार्य मानता है।यह बद्रिका के शंकराचार्य ह,लोग उनका प्रयागराज से वाराणसी तक उनका सम्मान करता है। 2027 का विधानसभा चुनाव प्रदेश की सभी 403 सीटों पर हम अपनी कार्यकर्ता सृजन के तहत तैयारी कर रहे है।सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का जैसा निर्णय होगा उसे पर काम किया जाएगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोग बता दें क्या कभी किसी संत महात्मा का हमारी सरकार में अपमान हुआ है,क्या कोई इस तरह के राजनीतिक दंगे हुए हैं,अगर हुए है तो हमको बता दें, कभी कोई मंदिर टूटा हो तो बता दें, हम लोग संत महात्माओं का सम्मान करते हैं उनका आशीर्वाद लेते है। योगी जी और मोदी जी बता दें यह खुद अपने आप को संत महात्मा से ऊपर समझते हैं इस कारण अब इनका जाने का समय आ गया है और अपना बोरिया बिस्तर बांध ले।उक्त बाते उन्होंने राकेश सिंह कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जिला कांग्रेश कमेटी के पिता जी स्व अमर बहादुर सिंह समाजसेवी के देहावसान के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव शुरू

जौनपुर,20 जनवरी। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव शुरू हो गए हैं। जौनपुर के दीवानी न्यायालय परिसर में 20 और 21 जनवरी को मतदान होगा। यह मतदान नई बिल्डिंग के मीटिंग हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदाताओं को अपनी पहचान सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) और रजिस्ट्रेशन प्रपत्र के साथ मीटिंग हॉल में उपस्थित कर्मियों से संपर्क करना होगा। मतदान के लिए कुल सात टेबल और 15 बूथ बनाए गए हैं, जिनकी संख्या मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ाई जा सकती है। किसी भी मतदाता को अस्त्र–शस्त्र, मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ मतदान स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी रणजीत कुमार और मुकीम अहमद ने इस संबंध में सूचना जारी की है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों का चयन होना है, जिसके लिए 333 प्रत्याशी मैदान में हैं। जौनपुर जनपद से भूपेश चंद्रवंशी, क्षितिज प्रियदर्शी, सचिन कुमार यादव, समर बहादुर यादव और तुलसीराम यादव सहित पांच प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जौनपुर में कुल 5734 मतदाता हैं। प्रत्येक मतदाता 25 मत दे सकता है, लेकिन न्यूनतम पांच मत देना अनिवार्य है। मंगलवार को मतदान शुरू होने से पहले जनपद के अधिवक्ताओं हिमांशु श्रीवास्तव, राजेश उपाध्याय, सूर्यमणि पाण्डेय, राजेश श्रीवास्तव, रघुवंश सहाय,विजय श्रीवास्तव, पंकज त्रिपाठी,आदि का कहना है कि इतने अधिक मतदाता होने के बावजूद जौनपुर से कोई प्रत्याशी नहीं चुना जाता। इस बार जौनपुर के अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि यहां से भी एक प्रतिनिधि चुना जा सके। यह प्रतिनिधि प्रदेश स्तर पर अधिवक्ताओं की समस्याओं और मांगों का समाधान करा सके अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना शामिल है।

मंडलायुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यो की मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न

संवाददाता ,बस्ती ।मंडलायुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यो की मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुयी। उन्होने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जल निगम, नियोजन, पंचायतीराज, पंचम वित्त राज आयोग, पर्यटन, लोकनिर्माण, लोक शिकायत, यू.पी.सी.एल.डी.ए.एफ., कृषि एवं सहकारिता, छात्रवृत्ति, जलजीवन मिशन, फैमिली आईडी, 15वॉ वित्त, ओडीओपी, फार्मर रजिस्ट्री सहित संचालित विकास योजनाओं की गहनता से समीक्षा किया। समीक्षा में उन्होने संचालित योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि मण्डल स्तरीय अधिकारीगण प्रगति में तेजी लाकर मण्डल की रैंकिंग को निचले स्तर से उच्च स्तर पर लाने का कार्य द्रुतगति से करें। उन्होने जलजीवन मिशन की समीक्षा में निर्देश दिया कि संचालित योजनाओं को शीघ्रअतिशीघ्र पूर्ण कराये। उन्होने छात्रवृत्ति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस कार्य को ससमय पूर्ण करायें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाय। उन्होने मुख्यमंत्री विवाह योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि सुरक्षा के दृष्टिगत अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होने बाढ़ से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ सुरक्षा से संबंधित सुधारध्सुझाव जनप्रतिनिधियों से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही अभी से प्रारम्भ कर दें। मण्डलायुक्त ने कहा कि आईजीआरएस मामलों के निस्तारण में बिना राग–द्वेष के सुस्पष्ट आख्या लगायें। अभिकथन के सापेक्ष पुष्टियुक्त साक्ष्य अवश्य संलग्न करें, जिससे शिकायतकर्ता को असंतुष्ट होने का मौका न मिलें। आईजीआरएस संबंधी मामलो में कार्यवाही संचालन अपर आयुक्त प्रशासन मनोज कुमार त्रिपाठी ने किया। बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने किया। बैठक में जिलाधिकारी बस्ती कृत्तिका ज्योत्स्ना, डीपीआरओ धनश्याम सागर, उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप, भूमि संरक्षण अधिकारी डा. राजमंगल चौधरी, एलडीएम आर.एन. मौर्य, वरिष्ठ सहायक सुहेल अहमद सहित मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

भूमि विकास बैंक अध्यक्ष पद चुनाव संपन्न, भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

संवाददाता

बस्ती। जनपद में भूमि विकास बैंक (सहकारी समिति) के अध्यक्ष पद का चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हर्रैया शाखा में दोपहर 12 बजे तथा बस्ती सदर शाखा में अपराह्न 1रू30 बजे ब्लॉक कार्यालय परिसर में नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी शाखा बस्ती से ओम प्रकाश त्रिपाठी एवं शाखा हर्रैया से श्याम बहादुर सिंह ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपने–अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। चूंकि किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, इसलिए चुनाव नियमों के अंतर्गत दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहले ही दोनों शाखाओं के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई थी। भाजपा प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन की खबर मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर ब्लॉक कार्यालय परिसर में कार्यकर्ताओं ने एक–दूसरे को मिठाई खिलाकर और फूल–मालाएं पहनाकर खुशी का इजहार

किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने दोनों नवनिर्वाचित अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भूमि विकास बैंक सहकारी समिति किसानों, सदस्यों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों अध्यक्ष पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए किसानों के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। इस अवसर पर ब्लाक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव, भानु प्रकाश मिश्र, आनंद सिंह कलहंस, अभिषेक कुमार, अमृत वर्मा, वीरेन्द्र गौतम, प्रबल मालानी, शिव चरण जायसवाल, सुखराम गौड़, शिव बहादुर मौर्या, नितेश सिंह, सुनील पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

महिला पुलिस ने छात्रों को दी पुलिसिंग कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी

अयोध्या। मंगलवार को साकेत महाविद्यालय तथा इन्वेंशन क्लासेज संस्था के छात्रों ने महिला थाना आकर पुलिस से संबंधित कार्यशैली के बारे में जानकारी हासिल किया। इस दौरान इन छात्रों ने महिला थाने

पर तैनात पुलिस कर्मियों से विभिन्न धाराओं, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लिया। बताते चले यह अभियान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व मे महिला थाना परिसर में चलाई गई।इस मौके पर महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे उप निरीक्षक संजीव मिश्रा, उप निरीक्षक श्वेता राठौड़ ,उपनिरीक्षक सोनी वहां पर उपस्थित छात्रों को थाने की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दिया।उनके अलावा इस मौके पर महिला आरक्षी प्रियदर्शिनी मिश्रा, महिला आरक्षी शकुंतला गौड़ व हेड मोहर्रिर चंद्रभान मौजूद रहे।

देवकाली पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

अयोध्या। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी व सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी पांडे के नेतृत्व में शहर के सभी चौकी

प्रभारी अपने–अपने क्षेत्र में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रहे हैं।इसी दौरान देवकाली पुलिस ने पुलिस के पकड़ से काफी दिनों से फरार चल रहा एक आरोपी को गिरफ्तार किया।इस संबंध में चौकी प्रभारी देवकाली एस एन सिंह ने बताया कि वे आरक्षी के साथ गस्त पर निकले थे। इस दौरान देवकली मंदिर के समीप डॉक्टर कृतांत सिंह के दीवार के पास आकाश बदमाश उर्फ आकाश यादव को गिरफ्तार किया उन्होंने बताया कि पुलिस को इस आरोपी की तलाश काफी दिनों से थी।उन्होंने उसकी आकाश बदमाश उर्फ आकाश यादव पुत्र स्व० रामलौट यादव निवासी चाँदपुर हरवंशपुर थाना पूराकलन्दर के रूप में हुई।

जिला सहकारी बैंक सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराए : संयुक्त आयुक्त सोमी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में विकास भवन सभागार में मंगलवार को सहकारिता विभाग की जनपद स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक वाराणसी मंडल सोमी सिंह ने किया। बैठक में जिला सहकारी बैंक को सहकारी समितियों के माध्यम से सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। संयुक्त आयुक्त सोमी सिंह ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता को जनपद में सहकारी समितियों में उर्वरक की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने श्सहकार से समृद्धिश की

दिशा में नए व्यवसाय शुरू करने, अधिक से अधिक नई समितियों का गठन कर उन्हें क्रियाशील बनाने और गुणवत्तायुक्त उर्वरक तथा अन्य व्यवसाय करने हेतु विभागीय अधिकारियों–कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए भी कहा। बैठक में ब्रजेश पाठक (एआर कोऑपरेटिव), आशुतोष त्रिपाठी (महाप्रबंधक, जिला सहकारी बैंक), सुधीर कुमार पाण्डेय (जिला प्रबंधक, पीसीएफ), रजनीश पाण्डेय, राधेश्याम यादव, अंकित काबरा, आशीष सिंह (एडीसीओ), ब्रह्म जीत सिंह, विपिन कुमार यादव (एडीओ) सहित जिला सहकारी बैंक जौनपुर के सभी शाखा प्रबंधक और अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

'ग्रामीण लघु उद्योग स्थापित कर आत्म निर्भर बने– सुनीता देवी'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' विगत दिवस राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की ओर से दो दिवसीय मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ग्राम पंचायत लेहना, न्याय पंचायत बखरिया, वि० खण्ड हरियावां में आयोजित कार्यक्रम का उदघाटन ग्राम प्रधान सुनीता देवी द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने लोगों को मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने पर जोर दिया व लघु उद्योग जैसे–पापड, अचार, कचरी, मसाला, आटा चक्की, पास्ता, दलिया, सेवई आदि उद्योग लगाने पर प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रभारी खाद्य निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार, अजीत सिंह व वृन्दावन बिहारी कषि वैज्ञानिक आदि ने इकाई लगाने के लिये प्रेरित किया व स्वयं का स्वरोजगार लगाने के लिये लोगों को प्रोत्साहित किया, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण से सम्बन्धित समस्त खाद्य सामग्री पर जानकारी दी तथा रोजगार लगाने के लिये प्रेरित किया। प्रभारी राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने बताया की मा० मुख्यमंत्री जी की दो दिवसीय मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना बहुत ही उत्कृष्ट योजना है इसमें कोई भी खाद्य प्रसंस्करण इकाई घरेलू स्तर पर लगा कर अपना स्वयं का रोजगार कर सकते है जिसमें सरकार की तरफ से योजना लागत का 50 प्रतिशत मशीन व उपकरण मद में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर कृषि विशेषज्ञ शिव प्रकाश सिंह वेबअन्य लोग मौजूद रहे।

आबकारी विभाग ने कई जगहों पर अवैध शराब कारोबारियो पर छापा मारकर की कार्यवाई

अयोध्या। मंगलवार को आबकारी विभाग ने कई जगहों पर अवैध शराब कारोबारियो पर छापा मारकर शिकंजा कसा।इस मौके पर भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब व लहन बरामद हुआ।इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी अयोध्या सुरेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि यह कार्यवाही आबकारी आयुक्त,डीएम व उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के कुशल

के निर्देश पर की गई।बताया कि जनपदीय व प्रवर्तन दल अयोध्या प्रभार की संयुक्त टीम द्वारा 'थाना–तारुन व कोतवाली बीकापुर अंतर्गत संदिग्ध ग्रामों–बालापुर, केशरुआ बुजुर्ग तथा जलालपुर माफी में अवैध शराब के निष्कर्षण, अनियमित व्यापार पर रोकथाम लगाये जाने हेतु आकस्मिक दबिश का आयोजन किया गया।छापे के दौरान दबिश कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया उक्त के अतिरिक्त लगभग 60 किलो तैयार लहन महुआ सहित अवैध शराब बनाने के उपकरण को भी बरामद किया गया।जिनमे से लहन का नमूना निकालकर शेष लहन को मौके पर नष्ट किया गया।प्रवर्तन कार्यवाही में अरविन्द, आनंद शुक्ला, विवेक पाठक (आबकारी निरीक्षक) सहित जनपद एवं प्रवर्तन दल के प्रधानध आबकारी सिपाही सम्मिलित रहे।'बताया कि अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

हिन्दू अध्ययन : सांस्कृतिक संवाद के साथ–साथ रोजगार को प्रोत्साहन

प्रो. एच. सी. पुरोहित
समन्वयक, हिन्दू अध्ययन केन्द्र,
दून विश्वविद्यालय, देहरादून

मनुष्य की सभ्यता की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारी चेतना, विकास और सांस्कृतिक पहचान का मूल स्रोत है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ जैसे दृ सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान और माया दृ न केवल अद्भुत स्थापत्य और विज्ञान की जननी रही हैं, बल्कि इन सभ्यताओं ने मानवता को नैतिकता, शासन, कृषि, लेखन और समाज व्यवस्था की नींव प्रदान की। इन सभ्यताओं का अध्ययन केवल अतीत को जानने के लिए नहीं, बल्कि आज की जटिल वैश्विक चुनौतियों का उत्तर खोजने का एक सशक्त उपाय भी है। उदाहरण के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था आज की जल–संकटग्रस्त दुनिया को टिकाऊ शहरी नियोजन का पाठ पढ़ा सकती है। मिस्र की स्थापत्य कला या मेसोपोटामिया की विधिक प्रणाली हमें यह दिखाती है कि मानव रचनात्मकता ने हजारों वर्ष पहले भी चमत्कारी समाधान खोजे थे। विश्वविद्यालयों और अध्ययन केंद्रों में इन प्राचीन सभ्यताओं पर केंद्रित शोध पुनः लोकप्रिय हो रहा है। जिसमें मुख्य रूप से 'हिन्दू स्टडीज', 'मेसोपोटामिया संस्कृति अध्ययन', 'मिस्रविद्या' और 'शास्त्रीय चीनी विचार' जैसे विशेष अध्ययन कार्यक्रम विश्वभर में विद्यार्थियों को संस्कृति, दर्शन, धर्म और प्रौद्योगिकी के ऐतिहासिक पहलुओं से परिचित करा रहे हैं। भारत में भी नवजागरण की तरह युवाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक विज्ञान को समझने की ललक बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों में मुख्य रूप से मातृभाषा को प्रोत्साहन देने के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित मूल्यवर्धक विषयों के शिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। यह समय है जब शिक्षा नीति, अनुसंधान संस्थान और मीडिया मिलकर इस चेतना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमें केवल विदेशी सभ्यताओं की ओर नहीं, बल्कि भारत की स्वयं की गौरवशाली विरासत जैसे दृ वेद, उपनिषदों के साथ ही, तक्षशिला, नालंदा शिक्षण संस्थानों व अरण्यक परंपरा, जिसमें आत्मविद्या ब्रह्मविद्या, उपासनाध्यान पर जोर दिया जाता है दृ की ओर भी देखना होगा। इसमें कर्मकांड से हटकर दार्शनिक और आध्यात्मिक विषय शामिल हैं। इस विरासत को विश्व पटल पर पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है।

मानव सभ्यता की आत्मा

धर्म को मानव सभ्यता की आत्मा माना जाता है। यह न केवल ईश्वर या आध्यात्मिकता से जुड़ा विषय है, बल्कि यह समाज, संस्कृति, नैतिकता, दर्शन और जीवन पद्धति का भी आधार है। विश्व के प्राचीन धर्म जैसे दृ वैदिक सनातन परंपरा, जरथुष्ट्र धर्म (पारसी), मिस्र का देवपूजन, यूनानी देवमाला, यहूदी परंपरा, मेसोपोटामिया के देवी–देवता, और ताओवाद आदि दृ आज भी मानव चेतना को गहराई से प्रभावित करते हैं।

आज जब आधुनिक सभ्यता भौतिक प्रगति की दौड़ में मानसिक और नैतिक द्वंद्वों से जूझ रही है, तब प्राचीन धर्मों का अध्ययन न केवल ऐतिहासिक या धार्मिक जिज्ञासा की पूर्ति करता है, बल्कि यह जीवन को संतुलन, करुणा और एकात्म दृष्टि प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी बन सकता है।

अध्ययन की प्रासंगिकता

हिन्दू अध्ययन से विश्व की विभिन्न सभ्यताओं को समझने एवं उनमें संवाद स्थापित करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से संस्कृति की समझ विकसित होगी क्योंकि हर समाज की सांस्कृतिक पहचान उसके धार्मिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ी होती है।

प्राचीन धर्मों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि सभ्यताओं ने जीवन, मृत्यु, प्रकृति, सृष्टि और आत्मा को कैसे परिभाषित किया। साथ ही यह वैश्विक संवाद और सह–अस्तित्व को प्रोत्साहित करेगा क्योंकि जब हम विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति और मूल विचारों को समझते हैं, तब हमें धर्मों के बीच साम्य और संवाद की क्षमता दिखती है। इससे वैश्विक शांति, सहिष्णुता और सह–अस्तित्व की भावना को बल मिलता है।

इसके अलावा धर्म और दर्शन का समन्वय भी विकसित होगा। भारत में धर्म केवल पूजा–पद्धति तक सीमित नहीं है, यह दर्शन, तर्क और योग की पद्धतियों से भी जुड़ा है। वेद, उपनिषद, जैन आगम, बौद्ध त्रिपिटक, और ताओवादी ग्रंथ जैसे 'ताओ ते चिंग' हमें जीवन की व्यापक समझ देते हैं जो नैतिक शिक्षा का भी स्रोत है। आज की पीढ़ी को यदि जीवन मूल्यों, कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ देनी है, तो प्राचीन ग्रंथों के विचारों से जुड़ना आवश्यक है।

शिक्षण संस्थानों की भूमिका

वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक धर्म, हिन्दू अध्ययन, बौद्ध दर्शन, अब्राहमिक धर्म और स्वदेशी आध्यात्मिकता जैसे पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। हिन्दू अध्ययन के अंतर्गत दृ हिन्दू परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, दर्शन, वेद, उपनिषद, स्मृति–शास्त्र, योग, पुराण, भक्ति वेदांत, भक्ति आंदोलन, धर्मशास्त्र, रामायण–महाभारत पर अध्ययन एवं शोध दृ मुख्य रूप से संचालित हो रहे हैं।

ईसाई धर्म केंद्र के अन्तर्गत दृ ईसाई धर्म का इतिहास, बाइबिल, धर्मशास्त्र, नैतिक दर्शन, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स परंपराएं, समाज, राजनीति, मध्यकालीन और आधुनिक ईसाई चिंतन एवं शोध शामिल हैं।

इस्लाम धर्म अध्ययन केंद्र के अंतर्गत – इस्लामी सभ्यता, इतिहास, दर्शन, संस्कृति, कानून, परंपरा, कुरान, हदीस, शरीयत और फिक्ह का गहन अध्ययन किया जाता है।

बौद्ध धर्म केंद्र के अन्तर्गत दृ बौद्ध धर्म की वैश्विक यात्राएँ, थेरवाद, महायान, वज्रयान परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन, पाली, तिब्बती और संस्कृत ग्रंथों पर शोध के साथ ही भाषायी–सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन होता है।

यहूदी धर्म अध्ययन केंद्र के अन्तर्गत दृ दर्शन, संस्कृति, तोराह, तलमूद, हिब्रू भाषा, यहूदी परंपराएँ, संगीत, कला, हिब्रू ग्रंथों पर अध्ययन व शोध शामिल हैं। इसी तरह सिख धर्म के दर्शन, संस्कृति, इतिहास, गुरुमुखी, कला, संगीत आदि पर शोध व अध्ययन कई संस्थानों में संचालित हो रहे हैं। भारत में दृ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सांची विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय सहित दर्जनों उच्च शिक्षण संस्थान प्राचीन धार्मिक परंपराओं पर उच्चस्तरीय शोध कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में शामिल करने का जो आह्वान किया गया है, वह इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। नवजागरण की आवश्यकता

प्राचीन धर्मों का अध्ययन एक निष्पक्ष, अकादमिक और तात्त्विक दृष्टिकोण से होना चाहिए, जिससे यह किसी संकीर्णता या प्रचार का साधन न बन जाए। यह अध्ययन हमारे युवाओं में जिज्ञासा, तर्क और सहिष्णुता को जन्म देगा।

प्राचीन धर्मों का अध्ययन केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए मार्गदर्शन और भविष्य के लिए चेतना का दीप है। जब हम विश्व के धार्मिक विचारों की विविधता को आत्मसात करते हैं, तब हम एक अधिक समावेशी, सह–अस्तित्व, वैश्विक शांति, वैज्ञानिक समझ के साथ संतुलित एवं समझदार समाज की ओर बढ़ते हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।